D

(21224)

LL.M. -I Sem.

Printed Pages : 7

Roll No. .....

L-46

LL.M. Examination, December -2024

INDIAN CONSTITUTIONAL LAW - I

(Fundamental Rights)

(L-1001)

Time : Three hours] *[Maximum Marks : 70*

Note: Attempt any five questions out of the following ten questions. Each question carries equal marks.

नोट : निम्नलिखित दस प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. In the modern world, the state has lot of functions to perform. In order to discharge its functions and duties, the state operates through certain agency or instrumentalities. The agencies or instrumentalities also fall within the scope of the expression 'State' as used in Article 12 of Indian Constitution. In the light of this fact, discuss the concept of 'State' as prescribed under Article 12 of Indian Constitution. Refer to decided cases.

Scanned with OKEN Scanner

आधुनिक विश्व में, राज्य के पास करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। अपने कार्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, राज्य कुछ अभिकर्ता या अभिकरणों के माध्यम से कार्य करता है। अभिकर्ता या अभिकरण भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्य' अभिव्यक्ति 'राज्य' के क्षेत्रविस्तार में आते हैं। इस तथ्य के आलोक में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत विहित 'राज्य' की अवधारणा की विवेचना कीजिए। निर्णीत मामलों का हवाला दीजिए।

2. Reservation policy is a tool of social justice. This policy has been incorporated Indian Constitution. Critically examine the relevance of this policy keeping in view the changing norms of the society. Refer to judicial pronouncements.

आरक्षण नीति सामाजिक न्याय का एक उपकरण है। इस नीति को भारतीय संविधान के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। समाज के बदलते मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों का हवाला दीजिए।

Scanned with OKEN Scanner

3. Freedom of press is implied from the freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a) of the constitution of India. How this freedom protected by Indian Judiciary? Discuss with the help decided cases.

प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय न्यायपालिका ने इस स्वतंत्रता को कैसे संरक्षित किया है? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

4. Right to life does not mean mere animal existence but it means right to live with human dignity. Comment. Refer to leading cases.

प्राण के अधिकार से तात्पर्य केवल पशुवत जीवन जीना नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य मानव गरिमा के साथ जीवन जीने से है। टिप्पणी कीजिए। मार्गदर्शक मामलों का हवाला दीजिए।

Scanned with OKEN Scanner

5. Doctrine of reasonableness and Doctrine of non-arbitrariness have been evolved by Indian judiciary to test the equality clause as prescribed under Article 14 of the Indian Constitution. With the help of decided cases discuss the relevance of these two doctrines.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत विहित समता खण्ड का परीक्षण करने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा युक्तियुक्तता के सिद्धान्त और गैर-मनमानेपन का सिद्धान्त को विकसित किया है। निर्णीत मामलों की सहायता से इन दोनों सिद्धान्तों की सुसंगतता की विवेचना कीजिए।

6. Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy are supplementary and complementary to each other. Comment with the help of decided cases.

मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। निर्णीत वादों की सहायता से टिप्पणी कीजिए।

Scanned with OKEN Scanner

7. Indian students have the right to receive education in their mother tongue and also preserve their cultural identity. Article 29 of the Constitution of India guarantees this right, while Article 30 protects the interest of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. In the light of this fact, discuss scope of Article 29 and 30 of the Indian Constitution.

भारतीय छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का भी अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 इस अधिकार को प्रत्याभूत करता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के हितों की रक्षा करता है। इस तथ्य के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के क्षेत्रविस्तार की विवेचना कीजिए।

Scanned with OKEN Scanner

8. Public interest litigation in such a constitutional remedy by which the judiciary has been successful to some extent in bringing about social charge. In view of this fact, explain the importance of public interest litigation in the present time. Refer to decided causes.

लोकहित वाद एक ऐसा संवैधानिक उपचार है जिससे न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन करने में कुछ सीमा तक सफल रही है। इस तथ्य के दृष्टिगत, लोकहित वाद का वर्तमान समय में महत्व को समझाइये। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।

9. With the help of decided cases, discuss the scope of individual religious freedom as guaranteed under Article 25 of the Indian Constitution.

निर्णीत मामलों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत वैयक्तिक धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्रविस्तार की विवेचना कीजिए।

Scanned with OKEN Scanner

10. In Maneka Gandhi case, Supreme Court has laid down that right to life means right to live with human dignity. Human dignity is quintessence of human rights. In this way, the court has opened a door of human rights jurisprudence under Indian constitution. Under this human rights jurisprudence, Indian judiciary has given many protections to criminals and hence evolved criminal justice system in the present day system. Refer to relevant decided cases.

मेनका गाँधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्राण के अधिकार से तात्पर्य मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से है मानव गरिमा मानव अधिकारों का सारांश है। इस प्रकार न्यायालय ने भारतीय संविधान के अन्तर्गत मानवाधिकार विधिशास्त्र का द्वार खोल दिया है। इस मानवाधिकार विधिशास्त्र के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका ने अपराधियों की कई सुरक्षाएं दी हैं और इस तथ्य के आलोक में, वर्तमान समाज में आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित हुई है। सुसंगत निर्णीत मामलों का हवाला दीजिए।

Scanned with OKEN Scanner